राजधानी लखनऊ, जौनपुर एवं भदोही से प्रकाशित

R.N.I NO - UPHIN/2002/23967

देश की उपासना

www.deshkiupasana.com & www.deshkiupasana.in

(हिन्दी साप्ताहिक)

वर्ष – 23 | अंक – 06 | लखनऊ, 12 जून 2025 | पृष्ठ – 08 | मूल्य – 2.00 रूपये

नया भारत शांति की रट नहीं लगाता...ऑपरेशन सिंदूर से मुंहतोड़ जवाब देता – मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष का कार्यकाल भारत वर्ष के स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाएगा। इस कार्यकाल में पीएम मोदी ने भारत को वैश्विक पहचान दी है। कांग्रेस समेत अन्य अस्थिर सरकारों में आमजन का विश्वास टूट गया था। वैश्विक स्तर पर भारत की छवि तार–तार हो गई थी। पीएम मोदी के भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और परिवारवाद से मुक्त नेतृत्व ने देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाकर अगले 25 वर्ष के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत की है। इन 11 वर्षों ने सामाजिक और संस्कृतिक पक्ष के साथ ही सेवा, सुशासन के साथ आर्थिक मोर्चे पर देश को एक नई पहचान दी है। शासन की नीति स्पष्टता, कार्य प्रणाली की पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही शासन की नई पहचान बनी है। विकास केवल नारे नहीं हैं। इन वर्षों ने विरासत और विकास का समन्वय करते हुए हुए देश को दुनिया में नई पहचान दिलाई। अब चेहरा

देख कर नहीं बल्कि जरूरत देख कर सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछले 11 साल में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस को हमने देखा है। यह 11 साल का समय उस वक्त पूरा हो रहा है जब भारत की सामरिक शक्ति को पूरे विश्व ने देखा है। पाकिस्तान में टेस्टेड और दुनिया में ट्रस्टेड भारत की सैन्य शक्ति मानी गई है। कोई हम पर युद्ध थोपेगा तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और आपरेशन सिंदूर से दिया जाएगा। अब भारत दुनिया में शांति की रट लगाने वाला देश नहीं है बल्कि युद्ध थोपने पर कड़ा जवाब देने वाला देश है।

देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में प्रस्तुत किया गया

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इन 11 वर्षों में भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में प्रदर्शित किया गया है। विकसित भारत के लिए पंच प्रण और 11 संकल्प बताए गए हैं। 11 साल में भारत ने विकसित भारत की आधारशिला पंच प्रण के आधार पर रखी है। समावेशी विकास शुरू किए गए हैं। ढांचागत विकास का मॉडल बनाया है। तकनीक के उपयोग के माध्यम से भ्रष्टाचार पर काबू पाया गया। पिछले 11 साल में जितना कुछ तकनीक के माध्यम से किया गया पिछले 65 साल में नहीं हो सका था। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति जातिवाद को भी बढ़ावा देती है। ऐसी पुनरावृत्ति फिर ना हो जिसकी वजह से पहले देश को गुलाम होना पड़ा था। मोदी सरकार के कार्यकाल में महिलाओं का नेतृत्व बढ़ाया गया है।

25–30 किमी0 दूरी से ही दुश्मन के हमलों को नाकाम कर देगी सरफेस–टू–एयर मिसाइल – रक्षा मंत्री राजनाथ

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्रालय जल्द ही सेना के लिए नई स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस–टू–एयर मिसाइल प्रणालियों की तीन रेजीमेंटों

की खरीद के लिए रू30,000 करोड़ के प्रस्ताव को प्रारंभिक मंजूरी देने के मामले पर विचार करेगा। रिपोर्टों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद इस माह के अंत में इन मोबाइल सरफेस–टू–एयर मिसाइल प्रणालियों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति देने पर विचार करेगी। हम आपको बता दें कि ये प्रणालियाँ दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलिकॉप्टरों और ड्रोन को 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक रोकने के लिए डिजाइन की गई हैं। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब भारत की मौजूदा बहु–स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली ने 'ऑपरेशन सिंदूर' (7 से 10 मई के बीच हुई झड़पों) के दौरान पाकिस्तान द्वारा छोड़े गए तुर्की मूल के ड्रोन और चीनी मिसाइलों के हमलों को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई थी। हम आपको बता दें कि पिछले तीन–चार वर्षों में डीआरडीओ और सेना ने सरफेस–टू–एयर मिसाइल प्रणालियों का विभिन्न प्रकार के खतरों और उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों के विरुद्ध परीक्षण किया है, ताकि दिन और रात दोनों स्थितियों में इनकी क्षमताओं का मूल्यांकन किया जा सके। बताया जा रहा है कि रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मिलकर इन प्रणालियों का निर्माण करेंगी। इन्हें टैंक और इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के साथ–साथ चलने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है ताकि सामरिक युद्धक्षेत्र में उन्हें हवाई सुरक्षा प्रदान की जा सके। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान असाधारण प्रदर्शन करने वाली आर्मी एयर डिफेंस को वास्तव में सरफेस–टू–एयर मिसाइलकी 11 रेजीमेंटों की आवश्यकता है। हालांकि सेना स्वदेशी आकाश प्रणाली की रेजीमेंटों को भी शामिल करती जा रही है, मगर वर्तमान में इसकी अवरोधन क्षमता लगभग 25 किमी है। हम आपको बता दें कि सरफेस–टू–एयर मिसाइल प्रणालियों का समावेश वायुसेना और सेना की मौजूदा वायु रक्षा नेटवर्क को और मजबूत करेगा। जहां तक सैन्य बलों के पास पहले से मौजूद प्रणालियों की बात है तो आपको बता दें कि इसमें रूसी एस–400 त्रिउम्फ लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है।

मानहानि केस में राहुल गांधी चाईबासा कोर्ट में 6 अगस्त को सशरीर हाजिर होंगे

रांची, एजेंसी। मानहानि से जुड़े मुकदमे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से थ्योड़ी मोहलतः मिली है। राज्य के चाईबासा स्थित एमपी –एमएलए कोर्ट की ओर से जारी गैरजमानती वारंट पर अब उन्हें 26 जून की बजाय 6 अगस्त को सशरीर हाजिर होना पड़ेगा। राहुल गांधी ने चाईबासा के एमपी–एमएलए कोर्ट की ओर से जारी वारंट को निरस्त करने और सशरीर उपस्थिति से छूट देने की मांग करते हुए जून के पहले हफ्ते में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसपर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के अधिवक्ता से पूछा कि जब चाईबासा कोर्ट ने पूर्व में उन्हें समन भेजा था, तो वे क्यों नहीं हाजिर हुए थे? इसी वजह से उनके खिलाफ कोर्ट को गैरजमानती वारंट जारी करना पड़ा, जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। इस पर राहुल गांधी के अधिवक्ता ने आग्रह किया कि उन्हें 26 जून को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है, लेकिन उस दिन कुछ जरूरी काम में उनकी व्यस्तता है। इसपर हाईकोर्ट ने अधिवक्ता का आग्रह स्वीकार करते हुए उन्हें अब 6 अगस्त को चाईबासा एमपी– एमएलए कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है। उल्लेखनीय है कि चाईबासा निवासी प्रताप कटियार नामक व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ 9 जुलाई, 2018 को दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2018 में

कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। शिकायत के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेस पार्टी के लोग किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह भाजपा में ही संभव है। इस शिकायत वाद पर चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ अप्रैल 2022 में जमानती वारंट जारी किया था।

संपादकीय

11 सालों के शासन का सर्वे

नरेन्द्र मोदी समेत पूरी भाजपा इस समय मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने की खुशियां मना रही है। इस मौके पर नरेन्द्र मोदी एक बार फिर नमो ऐप को सामने ले आए हैं, इस ऐप के जरिए वे जन मन सर्वे कर रहे हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इसकी जानकारी देते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोग इस पर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर अपनी राय सामने रखें और बताएं कि पिछले 11 बरसों में भारत के विकास पर उनकी क्या राय है। अक्सर सर्वे एजेंसियां चुनाव से पहले अलग–अलग मुद्दों पर इसी तरह सर्वे कराती हैं, जिनमें लोगों से शीर्ष पद के लिए उनकी पसंद से लेकर किन मुद्दों पर वोट करेंगे जैसे सवाल किए जाते हैं। पूछा जाता है कि मौजूदा सरकार को वे कितने अंक देंगे, दोबारा मौका देंगे या नहीं, विपक्ष के लिए क्या संभावनाएं हैं। फिर सर्वे से हासिल आंकड़ों के आधार पर दल चुनावों को लेकर अपनी रणनीति बनाते हैं। जनता के जवाब से उन्हें अपनी गलतियों का पता चल जाता है और गलती सुधारने का मौका भी रहता है।

लेकिन आजकल इसमें भी गफलत होने लगी है। अब राजनैतिक दल जनता पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भी सर्वे कराते हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष को ही शीर्ष पद के योग्य दिखाकर उसे पक्ष में माहौल बनाया जाता है। या चुनावों में नैरेटिव तय करने में इन सर्वेक्षणों को जरिया बनाया जाता है। चुनावों के वक्त जो ओपिनियन पोल होते हैं, यह भी इसी खेल का हिस्सा है। अर्थात निष्पक्ष सर्वे करवाकर वास्तव में जनता की राय जानने की जगह राजनैतिक दल जनता को मानसिक तौर पर प्रभावित करते हैं कि वह वही सोचे और कहे, जो ये चाहते हैं। आजकल ऐसे सर्वे में मीडिया की भी बड़ी भूमिका हो चुकी है। इस पृष्ठभूमि में देखें तो नमो ऐप के जरिए श्री मोदी जनता की जो राय लेना चाहते हैं, उसकी सार्थकता और सत्यता दोनों पर सवाल उठते हैं। पहली बात तो यही अजीब लगती है कि देश के प्रधानमंत्री को जनता की राय जानने के लिए अपने ही नामाक्षर के ऐप पर निर्भर होना पड़ता है। एक–दो साल नहीं पूरे 11 बरस से नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं और देश–विदेश में वे लगातार घूमते हैं। खास कर चुनाव प्रचार के क्त वे दिल्ली में कम और चुनावी राज्य में अधिाक दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वे चाहते हैं कि जनता उनके फैसलों का मूल्यांकन करे। दूसरी बात अपने काम पर प्रधानमंत्री जनता की मुहर लगवाना चाहते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन क्या उन्हें विपक्ष की आलोचना को सुनने की हिम्मत नहीं दिखाना चाहिए। हाल ही में पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक विपक्ष बार–बार संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर चुका है। दो–दो सर्वदलीय बैठकें हो गई हैं, लेकिन श्री मोदी एक भी बैठक में नहीं गए, न उन्होंने संसद का विशेष सत्र आयोजित किया। बल्कि अभी से मानसून सत्र की तारीख बता दी। जबकि संसद सत्र की तारीखें अमूमन हफ्ते भर पहले आती हैं, जो इस बार डेढ़ महीना पहले घोषित हो गईं। संसद में प्रधानमंत्री अपनी पूरी सरकार के साथ बैठें और विभिन्न फैसलों पर विपक्ष की राय सुनें तो उसी से 11 सालों का मूल्यांकन हो जाएगा। लेकिन ये रास्ता भी श्री मोदी ने नहीं चुना। तीसरी बात मीडिया के जरिए 11 बरसों का लेखा–जोखा हो सकता था।

पूर्वोत्तर को अराजकता में डाल सकती है हथियार नीति

ज्ञान

सरकार नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने की अपनी मूल जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है, और लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से कानून अपने हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। केंद्र और राज्य को अपनी सुरक्षा उपस्थिति बढ़ानी चाहिए और नागरिकों को हथियार देने की नीति को छोड़ना चाहिए। सरकार की सुरक्षा के अभाव में, नागरिकों के विशिष्ट समूह को हथियार देने का विचार सबसे खतरनाक खेल है। पूर्वोत्तर भारत में सबसे मुखर हिंदुत्व चेहरा, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विस्वा शर्मा, जिन्होंने अतीत में सांप्रदायिक आग को भड़काने का शौक दिखाया है, अब ऐसा लगता है कि उन्होंने हथियारों के संघर्ष की और भी भयानक आग के साथ खेलने का फैसला किया है, अगर राज्य में उनकी नयी हथियार नीति किसी भी तरह का संकेत देती है। उनके नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व वाली असम सरकार द्वारा नागरिकों के हाथों में अधिक हथियार देने का निर्णय पूरे पूर्वोत्तर में उग्रवादी और सांप्रदायिक हिंसा को और बढ़ायेगा, जो पहले से ही काफी समय से इस तरह के खतरे से पीड़ित है। हिमंत विस्वा शर्मा बांग्लादेश के पास सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वदेशी लोगों को हथियार देने के पक्ष में हैं। उन्होंने 29 मई, 2025 को स्पष्ट किया कि असम की नयी अस्त्र लाइसेंस नीति अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की सीमा से लगे क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी, क्योंकि ये क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील नहीं माने जाते हैं। उनके बयान से दो बातें उभर कर आईं – पहली, बांग्लादेश से लगे असम के सीमावर्ती क्षेत्र संवेदनशील हैंय और दूसरी, अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से लगे सीमावर्ती क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील नहीं हैं, हालांकि ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से सीमा विवादों और सशस्त्र संघर्षों में शामिल रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बांग्लादेश से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे सीमावर्ती क्षेत्र संवेदनशील रहे हैं, और उनकी सरकार स्पष्ट रूप से इसका संकेत देती दिखती है। सवाल यह है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देश के हर नागरिक के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी भारत के संविधान द्वारा दी गयी है, और सरकारें इसकी गारंटी लेती हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग केवल इसलिए असुरक्षित हैं क्योंकि केंद्र अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करने में अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा है, और असम सरकार अपनी सीमा के भीतर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा करने में असमर्थ है। केंद्र और असम में भाजपा सरकार हमेशा बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने की अपनी जिम्मेदारी विपक्ष पर डालने की कोशिश करती रही है, बार–बार देश को बताती रही है कि विपक्षी राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के लिए बांग्लादेश से मुस्लिम घुसपैठियों को अनुमति देते रहे हैं। भाजपा की डबल इंजन सरकारें क्या कर रही हैं – असम में 2016 से और केंद्र में 2014 से? बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोग यदि असुरक्षित हैं तो क्या यह उनकी सरकार की विफलता नहीं है? नागरिकों की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकारें अपनी शक्तिशाली प्रशिक्षित सेना और सशस्त्र पुलिस बल के साथ सुरक्षा नहीं दे सकती हैं, तो नागरिक केवल हथियारों की आपूर्ति से खुद की रक्षा कैसे कर सकते हैं? नागरिक न तो खुद की रक्षा कर सकते हैं और न ही अपने हथियारों की। हमने हाल ही में मणिपुर में इसे देखा है, जहां विद्रोही या उग्रवादी समूहों द्वारा सशस्त्र बलों से हथियार लूटे गये थे। असम के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से इससे कोई सबक नहीं लिया है। यही कारण है कि कैबिनेट नोट में कहा गया है कि नीति का उद्देश्य गैरकानूनी खतरों के लिए निवारक के रूप में कार्य करना और स्वदेशी समुदायों की व्यक्तिगत सुरक्षा और आत्मविश्वास में सुधार करना है। यह सरकार की गलत धारणा है, क्योंकि हमने पूरे देश में देखा है कि हथियार रखने वाले लोगों को उग्रवादी समूहों द्वारा केवल हथियार छीनने के लिए निशाना बनाया जाता है। हथियार आपूर्ति करने के बाद नागरिकों की सुरक्षा कौन करेगा? असम सरकार ने नयी हथियार नीति को मंजूरी देकर अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है कि सरकार के सुरक्षा बल सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों को सुरक्षा देने में असमर्थ हैं। शर्मा ने खुद कहा, श्बांग्लादेश में हाल ही में हुए घटनाक्रमों के कारण इन जिलों में मूल निवासी असुरक्षा के माहौल में रह रहे हैं। उन्हें बांग्लादेश की ओर से और यहां तक कि अपने ही गांवों से हमलों का खतरा है।श नयी हथियार नीति कथित तौर पर असम के धुबरी, नागांव, मोरीगांव, बारपेटा, गोलपारा और दक्षिण सलमारा–मनकाचर जिलों में लागू की जायेगी, जहां बांग्लादेश मूल के मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और मूल निवासी अल्पसंख्यक हैं। शर्मा ने कहा है, सरकार पात्र लोगों को हथियार लाइसेंस देने में उदारता बरतेगी, जो मूल निवासी होने चाहिए और मूल निवासी समुदायों से संबंधित होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? गैर–मुस्लिमों, स्वदेशी लोगों और मूल निवासियों यानी हिंदुओं को प्रभावी ढंग से हथियार मुहैया कराये जायेंगे। शर्मा ने जोर देकर कहा है कि नीति का उद्देश्य नागरिकों का सैन्यीकरण करना नहीं है।

संसद से भाग रही है मोदी सरकार

राजेंद्र

मोदी निजाम और उसके अंतर्गत संसद के अब तक के आचरण को देखते हुए, यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि सरकार ने अपनी तरफ से तो, पहलगाम की घटना और उसके बाद के घटनाक्रम पर फोकस्ड या विशेष रूप से केंद्रित बहस का रास्ता रोकने का मन बना लिया है। विशेष सत्र की मांग खारिज कर, सामान्य संसदीय सत्र को आगे किए जाने का, ठीक यही अर्थ है। आखिरकार, मोदी सरकार ने पहलगाम के आतंकवादी हमले और उसके बाद, श्आपरेशन सिंदूरश समेत पूरे घटनाक्रम पर संसद में अलग से चर्चा कराए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। बेशक, मोदी सरकार ने सीधे–सीधे इस मांग को नहीं ठुकराया है। सच तो यह है कि आधिकारिक रूप से तो उसने इस समूचे घटनाक्रम पर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की विपक्ष की लगभग पूरी तरह से एकजुट मांग को दर्ज तक करना जरूरी नहीं समझा है, तब इस मांग को स्वीकार किए जाने का तो सवाल ही कहां उठता था। मोदीशाही ने संसद के विशेष सत्र की मांग को ठुकराया है, संसद के आगामी मानसून सत्र की तारीखों की समय से पहले घोषणा करने के जरिए। सरकार के फैसले के अनुसार, संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से होने जा रहा है। कहने की जरूरत नहीं है कि संसद के विशेष सत्र तथा पूरे घटनाक्रम पर संसद में बहस की बढ़ती मांगों की ही काट करने के लिए, अभी से अगले सामान्य सत्र की तारीखों की घोषणा कर दी गयी है। प्रस्तावित सत्र से डेढ़ महीने से भी ज्यादा पहले, 4 जून को इन तारीखों के ऐलान से इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं रह जाती है कि संसद के विशेष सत्र की मांगों को खारिज करने के लिए ही, इतने पहले से प्रस्ताविक सामान्य सत्र की तरीखों का ऐलान किया गया है। सामान्यतः सत्र के शुरू होने की तारीख के ज्यादा से ज्यादा दो–तीन सप्ताह पहले ही, आगामी सत्र की तारीखों की घोषणा की जाती रही है। मोदी निजाम और उसके अंतर्गत संसद के अब तक के आचरण को देखते हुए, यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि सरकार ने अपनी तरफ से तो, पहलगाम की घटना और उसके बाद के घटनाक्रम पर फोकस्ड या विशेष रूप से केंद्रित बहस का रास्ता रोकने का मन बना लिया है। विशेष सत्र की मांग खारिज कर, सामान्य संसदीय सत्र को आगे किए जाने का, ठीक यही अर्थ है। इस तिकड़म के जरिए, न सिर्फ इस चर्चा के तत्काल आवश्यक होने को नकार दिया गया है, इसके सहारे इसे सामान्य संसदीय सत्र के अनेक अन्य मुद्दों में से एक बनाकर, मामूली बनाने की ही कोशिश की जाएगी। इस खेल को मणिपुर के घटनाक्रम पर संसद में बहस का जो हश्र हुआ था, उसके उदाहरण से समझा जा सकता है। केंद्रित बहस के बजाय, ज्यादा से ज्यादा एक सामान्य विस्तृत बहस की इजाजत दी जाएगी और हैरानी की बात नहीं होगी कि उसे भी खींच–खींचकर सत्र के अंत पर धकेल दिया जाए, जिससे सत्र का समापन इस विषय पर प्रधानमंत्री मोदी के लफ्फाजी भरे भाषण के साथ कराया जा सके। जिस तरह मणिपुर के मामले में संसद के किसी भी हस्तक्षेप का विफल होना सुनिश्चित किया गया था और यहां तक केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला लिया भी तो, उक्त बहस से लंबे अंतराल के बाद, राष्ट्रधारी पार्टी के अपने ही तकाजों से इसका फैसला लिया था। उसी प्रकार, पहलगाम और उसके बाद के घटनाक्रम पर, किसी भी जवाबदेही से सरकार को बचाने की ही कोशिश की जा रही होगी। ऐसा किसलिए किया जा रहा है, यह जानना मुश्किल नहीं है। इसके पीछे औपचारिक रूप से तो कोई तर्क ही नहीं है क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही कहा, सरकार ने विशेष सत्र बुलाने की मांग को सुना–अनसुना ही कर दिया है। बहरहाल, अनौपचारिक रूप से इसके पीछे जो तर्क काम कर रहा है, उसकी झलक हमें मोदीशाही की ट्रोल सेना से लेकर सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ताओं तक के अलग–अलग बयानों में दिखाई दे जाती है। इस तर्क का सार यही है कि विपक्ष को और जाहिर है कि उसके माध्यम से आम जनता को, सरकार द्वारा जो कुछ कहा–बताया गया है, उसके अलावा कुछ भी जानने की जरूरत ही क्या है? इसी तर्क का विस्तार है कि संसद में विपक्ष के नेता, राहुल गांधी द्वारा साढ़े तीन दिन के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय पक्ष को हुए नुकसान के बारे में सवाल पूछे जाने पर, इस तरह के सवालों को पाकिस्तान की आवाजश करार देकर, दबाए जाने की ही कोशिशें की गयी हैं। और शस्त्रविराम के पूरे महीने भर बाद भी आधिकारिक रूप से इस सैन्य कार्रवाई में भारतीय पक्ष के नुकसान की, खासतौर पर विमानों के नुकसान की, कोई जानकारी देना ही जरूरी नहीं समझा गया है। हद से हद उच्च सैन्य अधिकारियों की ओर से गोल–मोल तरीके से यह स्वीकार किया गया है कि, लड़ाई में नुकसान तो होता ही है। जाहिर है कि इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का यह ऐलान एक आसान बहाना बन गया है कि आपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ पॉज हुआ है। शस्त्रविराम के बाद भी लड़ाई जारी रहने की यह मुद्रा, किसी भी वास्तविक जवाबदेही के तकाजों के खिलाफ एक बड़ी ढाल बन जाती है। कहने की जरूरत नहीं है कि पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, सरकार से जवाब लिए जाने के लिए थोड़ा नहीं, बहुत कुछ है।

संक्षिप्त खबरें

विश्वनाथ धाम में दर्शन के नाम पर भक्तों से उगाही के आरोप में पकड़े गए 21 आरोपी

वाराणसी, संवाददाता। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कराने के नाम पर श्रद्धालुओं से उगाही करने के आरोप में एसीपी दशाश्वमेध डॉ. अतुल अंजान त्रिपाठी ने 21 लोगों को पकड़ा है। इस कार्रवाई से मंदिर के आसपास लोगों में खलबली मची है। बता दें कि पिछले कई महीने से काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के नाम पर उगाही का खेल चल रहा था। इसे लेकर अमर उजाला में पड़ताल के बाद प्रमुखता से खबर भी छापी गई थी। जिसके बाद से ही इस मामले में छानबीन चल रही थी।

ग्राम पंचायतों की सीटों पर नहीं हुआ बदलाव

गोरखपुर, संवाददाता। जिले में ग्राम पंचायत की सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा। जिला प्रशासन ने परिसीमन की सूचना जीरो करके भेज दी है। जिले में 1,275 पंचायत सीटें ही रहेंगी। हालांकि अब शासन को इस पर विचार करना है। जिला प्रशासन को शासन के आदेश का इंतजार है। शासन ने सभी जिलों से पंचायत परिसीमन की सूचना मांगी थी। शासन ने आदेश में ऐसी पंचायतों को शामिल करने के लिए कहा था जो निकाय विस्तार में प्रभावित हुई हों। उपनिदेशक पंचायत हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि 2022 में निकाय का विस्तार हुआ था। इसमें गोरखपुर की 21 पंचायतें खत्म हो गई थीं। कहा कि उस समय ही पंचायतों का परिसीमन कर दिया गया था। अब जिले में 1,275 पंचायत बची हैं। शासन को इसकी रिपोर्ट भेज दी है। अब शासन को ही निर्णय करना है।

फोरलेन पर सफाई कर रही महिला मजदूरों को ट्रक ने मारी टक्कर, तीन घायल

वाराणसी, संवाददाता। वाराणसी–बाबतपुर फोरलेन पर मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसे में तीन महिला सफाईकर्मी घायल हो गईं। सुबह करीब 9:30 बजे सातोमहुआ के पास तेज रफ्तार ट्रक ने सफाई कार्य में लगे मजदूरों और ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दिया। हादसे में तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रैक्टर चालक सुनील के अनुसार फोरलेन के डिवाइडर पर लगे सजावटी पौधों की छंटाई और डिवाइडर के पास जमा हुए मलबे की सफाई का कार्य कई दिनों से चल रहा है। मंगलवार को भी कार्यदायी संस्था की ओर से मजदूर तैनात थे। इसी दौरान वाराणसी से बाबतपुर की ओर जा रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने मजदूरों के साथ ही ट्रैक्टर को भी टक्कर मार दिया। हादसे में जंसा थाना क्षेत्र के भतसार गांव की निशा देवी और चंदा देवी तथा लहिया गांव की बिंदू देवी घायल हो गईं। तीनों महिलाओं को हादसे के बाद आनन–फानन में स्थानीय लोगों द्वारा नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ागांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया। इस बारे में थानाध्यक्ष बड़ागांव ने बताया कि दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया गया है।

यू–ट्यूब से सीख दबाई बच्चे के गले की नस, खतरे में पड़ी जिंदगी

प्रयागराज, संवाददाता। ऑनलाइन गेम किस कदर खतरनाक हो सकता है, इसकी बानगी कुंडा कमालापुर के देवीगंज गांव में सामने आई, जब यू–ट्यूब पर वीडियो देखकर एक किशोर ने खेल–खेल में बच्चे के गले की नस दबाई। इससे न सिर्फ बच्चा बेहोश हुआ, बल्कि उसकी जान खतरे में पड़ गई। गंभीर हालत में उसे प्रयागराज के निजी अस्पताल में न्यूरो सर्जन के पास लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ऑनलाइन गेम की लत में पड़कर कई बच्चे, किशोर और युवा जान गंवा चुके हैं। वहीं मोबाइल पर रील बनाने के लिए भी खतरों से खेला जा रहा है। ताजा मामले में मुंबई से कुंडा कमालापुर के देवीगंज गांव रिश्तेदारी में पहुंचे 11 साल के अहमान की जान खतरे में पड़ गई। दरअसल, शादी समारोह में माता–पिता के साथ पहुंचा अहमान चार–पांच दोस्तों के साथ यू–ट्यूब पर वीडियो देखकर गेम खेल रहा था। इसमें गर्दन की एक विशेष नस दबाने के बाद व्यक्ति बेहोश हो जाता है। इसके बाद गाल पर थप्पड़ मारने से उसे होश में लाया जाता है। जब यही ट्रिक एक साथी किशोर ने अहमान पर आजमाई तो वह भी बेहोश हो गया। दोस्तों ने थप्पड़ मारकर उसे होश में तो ला दिया, मगर अहमान को पैंट में बाथरूम होने तक का पता नहीं चला।

मुंह से निकल रहा था झाग

अहमान के परिजनों ने बताया कि जब उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो उसके मुंह से झाग निकल रहा था, पानी गले के नीचे नहीं उतर रहा था, वह चल–फिर भी नहीं पा रहा था और चेहरा लाल हो गया था। आनन–फानन उसे प्रयागराज में निजी चिकित्सक के पास ले जाया गया। यहां वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉ. प्रकाश खेतान ने बताया कि जब बच्चे का एमआरआई कराया गया तो देखा कि उसके दिमाग को ब्लड सप्लाई करने वाली कैरोटिड धमनी के दब जाने से दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। इस वजह से बच्चे को मिर्गी का दौरा आने लगा और उसका हाथ–पैर कमजोर पड़ गया था। पांच दिन उपचार के बाद बच्चा अब अपने पैरों पर चलने लगा है।

किशोर पहले भी कर चुका था इस तरह खतरनाक खेल

जिस किशोर ने अहमान के गले की नस दबाकर उसे बेहोश किया, वह पहले भी कई बार इस तरह यू–ट्यूब पर वीडियो देखकर खतरनाक खेल कर चुका है। जब उससे घटना के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि पहले भी कई बार लोगों को बेहोश कर वह दोबारा होश में ला चुका है। वह अक्सर मोबाइल पर वीडियो देखकर ऐसा खतरनाक गेम हकीकत में खेलता है। बताया जा रहा है कि वह यह सब रील बनाने के लिए भी करता है। इस प्रकार के कई मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर बच्चे ऑनलाइन गेम खेलकर जान जोखिम में डाल रहे हैं। अगर इस बच्चे को लाने में थोड़ी सी और देरी हो जाती, तो बच्चे की जिंदगी मुश्किल में पड़ सकती थी। फिलहाल बच्चा ठीक है और उसका इलाज चल रहा है।

बच्चों में हिंसात्मक गेम खेलने के कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में माता–पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चे को अगर मोबाइल देते हैं, तो कम से कम 18 वर्ष की उम्र तक कड़ी नजर रखें कि वह मोबाइल का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। समय–समय पर संवाद करें और बच्चों को आउटडोर गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करें।

सरयू में स्नान करते समय डूबीं चार किशोरियां, तीन को बचाया

बलिया, संवाददाता। बलिया जिले के मनियर थाना क्षेत्र पुरुषोत्तम पट्टी गांव के सरयू नदी में स्नान करने गई चार किशोरीयां डूब गईं। हालांकि नदी किनारे काम कर रहे मजदूर व बगल में स्नान कर रहे कुछ लोगों ने डूब रही चार किशोरियों में से तीन को किसी तरह से बचा लिया। जबकि एक किशोरी को बचाया नहीं जा सका। घटना की सूचना पाकर घाट पर काफी संख्या में लोग एवं पुलिस बल पहुंचा। काफी खोजबीन के बाद भी किशोरी का पता नहीं चल सका। इसके बाद पुलिस ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाया। दिन में दो बजे वाराणसी से आई एनडीआरएफ की 35 सदस्यीय टीम उपनिरीक्षक रामाज्ञा शुक्ला के नेतृत्व में डूबी किशोरी की तलाश में जुटी।

ये है मामला

जानकारी के अनुसार पुरुषोत्तम पट्टी गांव की चार किशोरियां मंशा (14), पिंकी (15), अंशा (14), हिमांशु (15) मंगलवार की सुबह करीब 7. 30 बजे सरयू नदी में स्नान करने गई हुई थीं। स्नान करते समय गहरे पानी में चली गईं। उनको डूबते देख कर आसपास मौजूद लोग व मजदूरों ने बचाने का प्रयास किया।

इस दौरान डूब रही तीन किशोरियों को बचा लिया गया। जबकि कुमारी हिमांशु यादव पुत्री शैलेंद्र यादव निवासी पुरुषोत्तम पट्टी का पता नहीं चल सका। जिसकी खोजबीन में स्थानीय मछुवारों के अलावा एनडीआरएफ की टीम जुटी है। बताया जा रहा है कि मंशा, पिंकी व अंशा गर्मी की छुट्टी में रिश्तेदारी में प्रीति यादव के यहां आई थीं।

उधर, जैसे ही परिजनों को घटना की जानकारी हुई, घर में कोहराम मच गया। मां–बाप की चीखें सुनकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भर आईं।

उधर, सूचना पाकर घटनास्थल पर तहसीलदार सिकंदरपुर प्रवीण सिंह, नायब तहसीलदार सीपी यादव, थाना प्रभारी मनियर रत्नेश कुमार दुबे भी पहुंच गए। थाना प्रभारी मनियर रत्नेश कुमार दुबे ने बताया कि लापता किशोरी की तलाश की जा रही है। इसके लिए एनडीआरएफ की टीम भी लगाई गई है।

रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार

भदोही, संवाददाता। भदोही जिले में नक्शा पास करने के नाम पर घूस लेने वाले भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) जेई को मिर्जापुर एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम ने जेई के साथ एक आउट सोर्सिंग कर्मचारी (डाक रनर) को भी पकड़ा है। आरोप है कि जेई द्वारा नक्शा पास कराने के नाम पर एक लाख 25 हजार रुपये रिश्वत मांगा जा रहा था। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण में नक्शा पास कराए जाने के नाम पर काफी समय से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। बीडा के क्षेत्र विस्तार के बाद यह और तेजी से बढ़ा है। भदोही कोतवाली के मूंसीलाटपुर निवासी नीरज कुमार गोंड को भवन निर्माण के लिए बीडा से नक्शा पास कराया जाना था। इसके लिए उन्हें बीडा में आवेदन किया। आरोप लगाया कि बीडा के जेई विनोद कुमार नक्शा पास करने के एवज में एक लाख 25 हजार रुपये मांग रहे हैं। जिस पर उन्होंने इसको लेकर एंटी करप्शन टीम मिर्जापुर से शिकायत की। मंगलवार को एंटी करप्शन की टीम ने तय रणनीति के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा रिश्वत की प्रथम किश्त 50 हजार रुपये के साथ बीडा कार्यालय पहुंची। एंटी करप्शन टीम के प्रभारी विनय सिंह के नेतृत्व में टीम ने घूस लेते हुए जेई विनोद कुमार के साथ एक आउट सोर्सिंग कर्मचारी अमित कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन टीम की दबिश की जानकारी होते ही बीडा कार्यालय में खलबली मच गई। टीम दोनों को गोपीगंज कोतवाली लेकर पहुंची। जहां आवश्यक कार्रवाई के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन टीम के प्रभारी विनय सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई थी।

शॉर्ट सर्किट से ठप हुई स्वास्थ्य सेवाएं, मरीज परेशान हो रहे

गोरखपुर, संवाददाता। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सोमवार को ट्रामा सेंटर के स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से करीब एक घंटे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इससे पेमेंट काउंटर के साथ इमरजेंसी में भर्ती की प्रक्रिया ठप पड़ गई। मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब एक घंटे बाद आपूर्ति बहाल होने पर मरीज के परिजनों ने राहत की सांस ली। मिली जानकारी के अनुसार, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सोमवार को ट्रामा सेंटर के स्विच बोर्ड में तेज आवाज हुई। इससे वहां की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। बिजली नहीं होने से यूजर चार्जेज काउंटर, इमरजेंसी भर्ती और इमरजेंसी पर्ची काउंटर पर होने वाले काम ठप पड़ गए। इससे स्वास्थ्य सेवाएं एक घंटे के लिए ठप हो गईं। इस दौरान मरीजों का ना ही पर्चा बन पाया और ना ही जांच के लिए यूजर चार्ज का भुगतान ही हो पाया। मामले की सूचना पर पहुंचे बिजलीकर्मियों ने फॉल्ट तलाशना शुरू किया। पता चला कि ज्यादा हीट होने से स्विच बोर्ड में लगे तार में शॉर्ट सर्किट हो गया है, जिससे आपूर्ति बाधित हो गई। आनन–फानन में बोर्ड की मरम्मत की गई। करीब एक घंटे बाद बिजली की आपूर्ति फिर से शुरू की जा सकी। प्राचार्य डॉ. रामकुमार जायसवाल ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण थोड़ी दिक्कत आ गई थी, जिसे समय पर ठीक करा लिया गया।

हाईकोर्ट के निकट फ्लाईओवर के नीचे चला अतिक्रमण हटाओ अभियान

प्रयागराज, संवाददाता। हाइकोर्ट के पास पुल के नीचे रविवार की आधी रात नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान न सिर्फ आसपास की दुकानें हटाई गईं, बल्कि पुल के नीचे रखे कुर्सी और टेबल भी निगम की टीम साथ ले गई। कार्रवाई के दौरान कैंट, सिविल लाइंस समेत कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद रही। आरोप है कि रोड पर अतिक्रमण कर कुर्सी–मेज रखे गए थे, जिससे दिनभर जाम की समस्या बनी रहती थी। रात करीब पौने 12 बजे नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ हाईकोर्ट पुल के पास पहुंची। इस दौरान हाईकोर्ट पानी टंकी से लेकर पुल के नीचे तक लगीं कुर्सियों को टीम ने जेसीबी से एकत्रित किया गया।

इसके बाद ट्रैक्टर ट्रालियों में लाद लिया, जिसे नगर निगम परिसर ले जाया गया। मौके पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इस बारे में आदेश जारी किए गए हैं। वहीं, मौके पर मौजूद लोगों ने जब पूछा कि टेबल–कुर्सी क्यों हटाया जा रहा है तो उन्हें जवाब मिला कि उनके पास सीनियर अधिकारियों के आदेश हैं। इस दौरान एसीपी सिविल लाइंस, एसपी कैंट, थाना प्रभारी समेत 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। सिविल लाइंस थाना प्रभारी रामाश्रय यादव ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है। दूसरी ओर नगर निगम कर्मियों का कहना था कि उच्चाधिकारियों के आदेश पर ही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम की कार्रवाई का अधिवक्ताओं ने विरोध किया। सोमवार को दिन में बड़ी संख्या में अधिवक्ता नगर निगम के कार्यालय पहुंचे नाराजगी जाहिर की। अधिकारियों से अधिवक्ताओं की तीखी नोकझोंक भी हुई।

डीडीयू के छात्र अब कर सकेंगे एआई और होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई

गोरखपुर, संवाददाता। प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों की तलाश कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अब शहर में ही कई सारे विकल्प मिल जाएंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय, एमएमएमयूटी में आगामी सत्र (2025–26) से नए कोर्स शुरू हो रहे हैं। इसमें डीडीयू में एआई, होटल मैनेजमेंट भी शामिल हैं। वहीं एमएमएमयूटी में बीटेक के छात्रों के लिए गीता, वैदिक गणित व कई अन्य कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आगामी सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डाटा साइंस, एमसीए, होटल मैनेजमेंट में मास्टर्स, कंप्यूटर साइंस में एमटेक, जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स और कैपिटल मार्केट में पीजी डिप्लोमा कोर्स की पढ़ाई होगी। एमएमएमयूटी में बीटेक के छात्र गीता, वैदिक गणित व अन्य कोर्स में आसानी से प्रवेश ले सकेंगे। इससे उन्हें एक दूसरे जगह कोर्स के लिए नहीं जाना होगा।

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खाद्य पदार्थों और दवाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए सेंटर फॉर फूड एंड ड्रग टेक्नोलॉजी बनेगा। इसमें शोधार्थियों को शोध के अवसर मिलेंगे। साथ ही कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग विभाग के छात्र एडवांस्ड साइबर फॉरेंसिक लैब में नई तकनीकी सीख सकेंगे।

साइबर अपराधों में उपयोग होने वाली तकनीक जैसे मैलवेयर या हैकिंग टूल्स साइबर अपराधी अक्सर अपनी पहचान छिपाने के लिए वीपीएन, टोर नेटवर्क, या फर्जी खातों का उपयोग करते हैं। इससे उनकी पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए साइबर फॉरेंसिक लैब में छात्रों को नई तकनीकी से अवगत कराया जाएगा।

आने वाले समय में छात्रों की जरूरतों को देखते हुए इन कोर्स को शुरू किया गया है। ताकि उन्हें एक ही जगह सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

विश्वविद्यालय के छात्रों को नई तकनीकी से जुड़ने का मौका मिले। प्रतियोगिता के दौर में छात्रों को नई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा

हाईटेंशन लाइन की करंट के चपेट में आकर सगे भाइयों की मौत

बस्ती, संवाददाता। लुंबिनी– दुद्धी मार्ग पर नगर थानाक्षेत्र के खुटहन के पास मंगलवार सुबह करीब नौ बजे लोहे की सीढ़ी ले जा रहे सगे भाई हाई टेंशन करंट की चपेट में आ गए। जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना के विरोध में गांव के लोग हाईवे जाम करके बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। कुछ देर बाद पुलिस ने उन्हें समझा–बुझाकर हटाया। बताया जा रहा है कि 26 वर्षीय शशि भूषण इसी क्षेत्र के बक्सर के एक निजी विद्यालय में पढ़ाते थे। मंगलवार को घर पर लोहे की सीढ़ी की जरूरत थी। अपने सगे भाई 23 वर्षीय विश्वबल्लभ के साथ बाइक से सीढ़ी लेकर लौट रहे थे। सड़क से मुड़ते ही सीढ़ी तार में छू गई।

संक्षिप्त खबरें

वीडीए बोर्ड के सदस्य और अधिकारी के बीच जमकर हुई बहस

वाराणसी, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी और वीडीए बोर्ड के सदस्य अंबरीश सिंह भोला की एक अधिकारी के साथ जमकर बहस हुई। विवाद वाराणसी के पहड़िया मंडी में एक दुकान को खाली कराने को लेकर शुरू हुआ। काफी देर चक चली बहस के दौरान भोला ने मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात कही है।

खुद पर डाला डीजल, लगा चिल्लाने– कर्मचारियों ने बचाई जान

महराजगंज, संवाददाता। जमीनी विवाद को लेकर एक युवक ने मंगलवार को दिन में तहसील परिसर में एसडीएम कार्यालय के सामने अपने उपर डीजल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। जिससे परिसर में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने युवक को बचाया। युवक चिल्ला चिल्ला कर प्रशासन की लापारवाही की बात कह रहा था। फरेंदा थाना क्षेत्र के सिधवारी निवासी सुरेंद्र यादव न्याय न मिलने व अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर लगाकर थक हार गया था जिससे वह क्षुब्ध था। आरोप है कि फरेंदा धानी मार्ग पर हाइवे पर उसकी भूमि है, जिसमें वह आधे का हिस्सेदार है। जिसका न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। लेकिन विपक्षी जबरन उसकी भूमि में पेट्रोल पंप लगाने का प्रयास कर रहे है। भूमि पर कब्जा को रोकने के लिए वह अधिकारियों के कार्यालयों का चक्कर लगा रहा है। जबकि पुलिस भी मामले को लेकर लीपापोती में लगी हुई है। लेकिन उसकी कोई सुनवाई नही हो रही है और आरोपी कब्जा करने में लगे हैं।

डबल चेक सिस्टम से जमा होगी फीस, सीएमएल और पीएमएल से तय होगा प्रवेश

वाराणसी, संवाददाता। बीएचयू के परा स्नातक प्रवेश प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन कराने का आज अंतिम दिन रहा। अब काउंसिलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं, इस बार फीस के भुगतान में कोई गलती न हो, इसके लिए डबल चेक सिस्टम लाया गया है। यानी कि पैसा कटने से पहले दो मैसेज आएंगे।

इसके अलावा प्रवेश से पहले दो–दो मेरिट लिस्ट तैयार होगी। एक समग्र मेरिट लिस्ट (सीएमएल) और दूसरी प्रोग्राम वाइज मेरिट लिस्ट (पीएमएल)। सीटों के आवंटन के समय सभी योग्य अभ्यर्थियों को समग्र मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। वहीं, पीएमएल में सिर्फ उन्हें ही जगह दी जाएगी, जो संबंधित कोर्स के लिए विशेष पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। इसके तहत कोर्स की विशेषज्ञता के आधार पर आवेदकों की योग्यता जांची जाएगी। बीएचयू की ओर से कंबाइंड एलॉटमेंट प्रोग्राम जारी कर कहा गया है कि सभी अभ्यर्थी अपना पोर्टल और डैशबोर्ड चेक करते रहें। जैसे ही मेरिट लिस्ट में नाम आता है और सीट आवंटित हो जाती है तो जल्द से जल्द फीस जमा करने की सूचना पोर्टल पर मिलेगी। वहीं, कॉलेज या परिसर अपग्रेड करने पर प्रवेश शुल्क को एडजस्ट किया जाएगा।

लुटेरी दुल्हन गैंग ने तीन साल में की 50 लाख की ठगी किया

प्रयागराज, संवाददाता। शादी, रिश्तेदारी और भरोसे को हथियार बनाकर ठगी करने वाले लुटेरी दुल्हन गैंग के सदस्यों से पूछताछ के दौरान बेहद सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पता चला है कि यह गिरोह पिछले तीन वर्षों से सक्रिय था और अब तक 30 से ज्यादा कुंवारे युवकों और उनके परिवारों को फर्जी शादी के जाल में फंसा कर करीब 50 लाख रुपये की ठगी कर चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में शामिल श्रीराम गुर्जर इस गिरोह का अहम सदस्य है जो एक एजेंट के रूप में काम करता था। वह राजस्थान व अन्य राज्यों में घूमकर भोले–भाले युवकों को 'अच्छी लड़की' दिलाने का झांसा देता और गैंग तक लेकर आता। प्रत्येक फर्जी शादी के बदले उसे 20 से 25 हजार रुपये का कमीशन और सफर का खर्च मिलता था। उसकी खुद की शादी भी प्रयागराज में हुई थी, जिससे उसका यहां लगातार आना–जाना बना रहता था। सबसे बड़ी बात है कि वह इस गिरोह का अकेला एजेंट नहीं। उसके जैसे कई और एजेंट गिरोह ने बना रखे थे जो कमीशन लेकर फर्जी शादी करने के इस खेल में शामिल हैं।

दुल्हन का भाई खुद को बताने लगा प्रेमी, दूल्हे के उड़े होश

खुल्दाबाद में मामले के भंडाफोड़ के दौरान एक और बात सामने आई। गिरफ्तार लोगों में शामिल अमन उर्फ आसिफ शादी के वक्त खुद को दुल्हन का भाई बताता रहा और रस्में भी निभाई। कुछ देर बाद जब परिवार दुल्हन को लेकर वापस जाने लगा तो पानी की टंकी ओवरब्रिज के नीचे रास्ते में जबरन कार रोक ली। इसके बाद दुल्हन को कार से उतारकर वह उसे अपनी प्रेमिका बताने लगा। यह सुनकर दूल्हे व उसके परिवारवालों के होश उड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह हो क्या रहा है। बाद में दुल्हन समेत सभी के फरार होने पर उन्हें माजरा समझ आया। यह खुलासा खुद दूल्हे के पिता गोपाल गुर्जर ने पुलिस के सामने किया।

पुलिस की कार्रवाई तेज, अंतरराज्यीय कनेक्शन की जांच

खुल्दाबाद पुलिस ने अब इस गिरोह की जांच तेज कर दी है। गिरोह के सदस्यों के बैंक खातों, कॉल रिकॉर्ड और यात्रा विवरण भी खंगाले जा रहे हैं। आशंका इस बात की भी है कि गिरोह का जाल यूपी, राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों में भी हो सकता है। पिछले साल इसी गैंग ने नैनी में मुजफ्फरनगर के अमन सिंह को शिकार बनाया था। उससे भी शादी के नाम पर 1.4 लाख रुपये ऐंठे गए थे और बाद में लौटते वक्त रास्ते में मारपीट कर मोबाइल, लाखों के जेवर लूटने के बाद गिरोह के सदस्य दुल्हन को लेकर फरार हो गए थे। यह एक सुनियोजित ठग गिरोह है जो शादी के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहा था। गिरफ्तार सदस्यों में शामिल प्रीति पहले भी जेल जा चुकी है। गैंग के कनेक्शन को खंगाला जा रहा है।

घर नहीं दिखाया, बोले पड़ोसी की मौत हो गई है, मंदिर में करेंगे शादी

पीड़ित दूल्हे के पिता गोपाल गुर्जर ने एक और अहम बात बताई। बताया कि प्रयागराज आने से पहले तय था कि विवाह दूल्हन के घर पर होगा। प्रयागराज पहुंचते ही खुद को दुल्हन की मौसी बताने वाली महिला व उसके साथ आए अन्य लोगों ने कहा कि उनके पड़ोसी की मौत हो चुकी है। ऐसे में वहां नहीं जाया जा सकता। अब शादी मंदिर में होगी।

ट्रेन में महिला ने दिया बच्चे को जन्म

प्रयागराज, संवाददाता। वाराणसी से अनूपपुर जंक्शन जा रही एक महिला यात्री ने सारनाथ एक्सप्रेस में एक बच्चे को जन्म दिया। आपरेशन मेरी सहेली की टीम ने महिला सिपाहियों की मदद से चादर का घेरा बनाकर कोच में ही महिला का प्रसव कराया गया। गाड़ी के प्रयागराज जंक्शन पहुंचने पर महिला को उताकर जिला महिला चिकित्सालय (डफरिन) भेजा गया। जिस पर उप निरीक्षक गौरव व 7– 10 प्लेटफार्म ड्यूटी में तैनात महिला कांस्टेबल मोनिका व ऑपरेशन मेरी सहेली में तैनात महिला कांस्टेबल सपना राय ने कॉमर्शियल स्टाफ व मेडिकल स्टाफ के साथ गाड़ी संख्या 15159 के एस–2 में बर्थ नंबर 78 पर पहुंच गए।

लखनऊ विश्वविद्यालय- 40 क्रेडिट का होगा एक वर्षीय परास्नातक कोर्स

लखनऊ, संवाददाता। लखनऊ विश्वविद्यालय का एक वर्षीय परास्नातक कोर्स 40 क्रेडिट का होगा। इसमें दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को प्रति सेमेस्टर 20 क्रेडिट मिलेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और नई शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत पीजी इस शैक्षणिक सत्र पाठ्यक्रम के लिए तय गाइडलाइन के हिसाब तैयार किए गए पीजी अध्यादेश को लखनऊ विश्वविद्यालय ने स्वीकृति दे दी है। एक वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रारूप को लेकर विवि जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा। लविवि में वर्तमान में दो वर्षीय पीजी पाठ्यक्रम संचालित है। नए शैक्षणिक सत्र से छात्रों को एक वर्ष का पीजी कोर्स करने की भी सुविधा मिलेगी। हालांकि, इसके लिए चार वर्षीय स्नातक करने वाले छात्र–छात्राओं को 75 प्रतिशत से ऊपर अंक लाने होंगे। इससे कम अंक वालों के लिए दो साल का ही पीजी कोर्स करने का विकल्प रहेगा। डीन एकेडमिक्स प्रो. गीतांजलि मिश्रा के मुताबिक अभी तक दो साल के पीजी कोर्स में प्रति सेमेस्टर छात्र को 24 क्रेडिट दिए जाते थे, लेकिन नए अध्यादेश में प्रति सेमेस्टर 20 क्रेडिट मिलेंगे। यह है क्रेडिट सिस्टम– एनईपी में क्रेडिट सिस्टम किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम को मापने का व्यवस्थित तरीका है। यह किसी विषय से संबंधित कार्यभार है, जिसमें तय होता है कि छात्र को कितना अध्ययन करना है। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी को एक प्रणाली में 14 क्रेडिट हासिल करने के लिए प्रयोगशाला में 28 घंटे पूरे करने होते हैं। यहां दो घंटे के प्रैक्टिकल में उसे एक क्रेडिट दिया जाता है। लविवि की डीन एकेडमिक्स प्रो. गीतांजलि ने बताया कि एक वर्षीय परास्नातक कोर्स में विद्यार्थी को 40 क्रेडिट पढ़ने होंगे, जबकि दो वर्ष के पीजी में 80 क्रेडिट। पहले दो वर्षीय पीजी 96 क्रेडिट का होता था। यूजीसी के मुताबिक, एक क्रेडिट में विद्यार्थी को 15 घंटे पढ़ना होता है और सेमेस्टर में 15 सप्ताह। विद्यार्थी कितने घंटे पढ़ाई करेगा यह क्रेडिट पर निर्भर होगा। चार क्रेडिट का होता है एक पेपर रू लविवि में एनईपी के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों में एक पेपर के लिए अधिकतम चार क्रेडिट और न्यूनतम दो क्रेडिट निर्धारित हैं। यानी विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में एक पेपर को 60 घंटे पढ़ना होगा। प्रैक्टिकल पेपर में यह संख्या ठीक दोगुनी हो जाती है।

जमीन के नाम पर मेजर से 72 लाख रूपये की ठगी

लखनऊ, संवाददाता। आशियाना निवासी सेना की मेजर जीजी विजयन ने विश्वजीत सिंह, विजय सिंह, आरती सिंह व अनिल पर उनसे जमीन के नाम पर 72 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व विश्वासघात की धारा में एफआईआर दर्ज की है। जीजी विजयन के मुताबिक वर्ष 2020 में वह मकान खरीदना चाहती थीं। इस संबंध में आशियाना निवासी विश्वजीत सिंह व विजय सिंह से मुलाकात हुई थी। विश्वजीत ने हिंद नगर के कासिमपुर पकरी में एक जमीन दिखाई थी, जिसका सौदा 72 लाख रुपये में तय हुआ था। 16 मई 2020 को मेजर ने आरोपियों को भुगतान कर दिया था। इसके कुछ दिन बाद जब वह जमीन पर निर्माण करा रही थीं, तभी एलडीए कर्मचारियों ने उन्हें रोक दिया। बताया कि एलडीए से जमीन का वाद चल रहा है। मेजर ने जब आरोपियों से रकम मांगी तो विश्वजीत के साले अनिल ने धमकी दी तब पुलिस ने सुनवाई नहीं की। इसके बाद मेजर लंबे समय के लिए शहर से बाहर चली गईं। अब लौटीं तो पुलिस आयुक्त से शिकायत की, जिसके बाद केस दर्ज किया गया। इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह के मुताबिक मामले की विवेचना की जाएगी।

आप सांसद संजय ने यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं पर उठाए सवाल

लखनऊ, संवाददाता। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने बदायूं के महिला अस्पताल का जिक्र करते हुए कहा कि यहां पर सीपैक वेंटिलेटर न होने से हर महीने 25 से 30 बच्चों की मौत हो रही है। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। मीडिया खबरों के मुताबिक यहां पर सीपैक का वेंटिलेटर लाया गया पर इसे चलाने के लिए स्टाफ को प्रशिक्षण नहीं दिया गया और बच्चों की मौत होती रही। यह शर्मनाक है कि अस्पताल के स्टाफ को इतने समय में ट्रेनिंग तक नहीं दी जा सकी। यह आपराधिक लापरवाही है। जो भी जिम्मेदार हैं सरकार को उन पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना में घोटाला हो रहा है। मामले में हजरतगंज में मुकदमा दर्ज किया गया है।

6239 मरीजों के नाम पर 39 अस्पतालों को 10 करोड़ का भुगतान कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर के अस्पताल में एक्सरे फिल्म पर न देकर कागज पर दिया जा रहा है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है।

संजय सिंह ने बीबीसी की एक रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि कुंभ में 82 लोगों की मौत हो गई लेकिन सरकार ने मृतकों के आंकड़े छिपाए हैं। सरकार ने जानबूझकर भगदड़ में मृतकों की कम संख्या दिखाई।

संक्षिप्त खबरें

मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा करेगा सम्मेलन

लखनऊ, संवाददाता। यूपी भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुँवर बासित अली के संयोजन में होने वाले इस कार्यक्रम में श्मोदी के साथ मुसलमानश विषय पर चर्चा होगी। 12 जून को शाम चार बजे अटल बिहारी बाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में होने वाले इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होंगे। बासित अली ने बताया कि विकसित भारत का अमृतकाल एवं सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष पूर्ण होने पर इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मोदी सरकार बनने के बाद मुसलामनों की जिंदगी में आए सकारात्मक बदलावों की चर्चा होगी। मालूम हो कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भाजपा में जिले और प्रदेश स्तर पर विभिन्न आयोजन हो रहे हैं।

पीजीआई डॉक्टर सहित बीते 24 घंटे में आए कोविड के तीन नए मामले

लखनऊ, संवाददाता। राजधानी में बीते 24 घंटे में तीन नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसमें पीजीआई के डॉक्टर भी शामिल हैं। 42 साल के पुरुष और 27 साल की महिला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तीनों ही संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री है। पीजीआई के क्लीनिकल इम्यूनोलॉजी विभाग के 57 साल के डॉक्टर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 25 मई को वो गाजियाबाद गए थे। लौटने पर उन्हें बुखार के साथ जुकाम की शिकायत हुई। जांच कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वह होम आइसोलेशन में हैं।

लक्षण दिखने पर कराई जांच

सीएमओ कार्यालय से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, नए मरीजों में बादशाह नगर के पेपर मिल कॉलोनी निवासी 42 साल के पुरुष की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनकी दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री है। उन्हें 5 जून से लगातार बुखार आ रहा है। निजी लैब में जांच कराने के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिलहाल होम आइसोलेशन में उनका इलाज चल रहा।

गोमती नगर निवासी युवती की रिपोर्ट आई पॉजिटिव

लखनऊ के विनीत खंड गोमतीनगर निवासी 27 साल की युवती की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है।

युवती की दिल्ली की ट्रैवल हिस्ट्री है। 30 मई से 6 जून तक वो दिल्ली में रही। 6 जून को तेजस ट्रेन से उन्होंने लखनऊ की वापसी की। इस बीच लगातार बुखार और जुकाम जैसे लक्षण थे। जांच के लिए सैंपल देने के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनका भी फिलहाल होम आइसोलेशन में चल रहा इलाज।

बिरजू महाराज कथक संस्थान के विद्यार्थियों ने किया सामूहिक सूर्य नमस्कार

लखनऊ, संवाददाता। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में चल रही आयोजनों की शृंखला में योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ की थीम पर बिरजू महाराज कथक संस्थान में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। संस्थान के परिसर में योगाचार्य डॉ. हंस कुमारी ने सूर्य नमस्कार से स्वास्थ्य को होने वाले लाभ के बारे में बताया। उनके निर्देशन में विद्यार्थियों ने सूर्य नमस्कार की सभी मुद्राओं का अभ्यास किया।

हज यात्रा 2025 – अब नियमों में होगा बदलाव

लखनऊ, संवाददाता। सऊदी अरब में हज मुकम्मल करने बाद वतन वापसी के समय हाजी अपने साथ 55 किलोग्राम सामान ला सकेंगे। हाजियों की वतन वापसी बृहस्पतिवार से शुरू होगी। हाजियों की पहली उड़ान अब रात 12:25 बजे राजधानी के चौधरी चरण सिंह हवाई अडडे पर पहुंचेगी। इस उड़ान का समय पहले 7:35 बजे तय था। इसी दिन दूसरी उड़ान सुबह 5:45 बजे चौधरी चरण सिंह हवाई अडडे पर पहुंचेगी। प्रदेश से इस बार कुल 13685 हज यात्री सऊदी अरब रवाना हुए हैं। इसमें 7278 पुरुष व 6407 महिलाएं शामिल हैं। राजधानी के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से कुल 5522 हज यात्रियों को मदीना मुनव्वरा भेजा गया है। सऊदी अरब में हज के सभी अरकान अदा हो चुके हैं।

हज मुकम्मल कर चुके सभी हज यात्री अब हाजी कहे जाएंगे। प्रदेश के हाजियों की वतन वापसी बृहस्पतिवार से शुरू होगी। सऊदी अरब से हाजियों को लेकर आने वाली पहली उड़ान के समय में बदलाव किया गया है।

चिनाब ब्रिज के आसपास हैं ये खूबसूरत जगहें, जन्नत सा दिखता है नजारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जम्मू–कश्मीर में चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। 1315 मीटर लंबा चिनाब ब्रिज दुनिया के सबसे ऊंचे पुल में शुमार है और एफिल टावर से भी ऊंचा है। इस पुल के बनने के बाद जम्मू तवी से कटरा होते हुए श्रीनगर तक रेल मार्ग के जरिए पहुंचना काफी सरल हो जाएगा और यात्रा में वक्त भी कम लगेगा। अभी तक भारतीय रेलवे केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू तक ही सीमित था। ट्रेन का टिकट बुक करने पर जम्मू कश्मीर जाने वाली ट्रेन राजधानी श्रीनगर तक नहीं, बल्कि जम्मू तवी तक ही जाती थीं। इसके आगे का रास्ता लोगों को सड़क मार्ग के जरिए श्रीनगर (कश्मीर घाटी) तक तय करना होता था। जम्मू तवी से श्रीनगर की दूरी लगभग 350 किमी दूर है। जिसका सफर तय करने में लगभग छह घंटे लग जाते हैं। हालांकि ठंड के मौसम में बर्फबारी के बाद रास्ते बंद होने का खतरा रहता है, जिससे कश्मीर तक जाने के लिए मौसम के ठीक होने का इंतजार किया जाता है या फिर भारत के किसी भी शहर से हवाई मार्ग का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन अब जम्मू तवी से श्रीनगर तक रेल मार्ग के जरिए पहुंच सकते हैं। अगर आप वैष्णो देवी धाम गए हैं तो कटरा से कश्मीर की रेल यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा चेनाब रेलवे ब्रिज के पास कई और खूबसूरत स्थल हैं, जहां का नजारा आप ट्रेन के यात्रा के दौरान तो देख ही सकते हैं। साथ ही अगर आप इन्हें करीब से देखना चाहते हैं तो वहां तक पहुंच भी सकते हैं। आइए जानते हैं चेनाब रेलवे ब्रिज के पास स्थित अदभुत सौन्दर्य वाली इन शानदार जगहों के बारे में।

चेनाब ब्रिज के पास घूमने लायक खूबसूरत जगहें

कटरा

चेनाब रेलवे ब्रिज की यात्रा श्री वैष्णो देवी धाम कटरा रेलवे स्टेशन से ही शुरु होती है। चेनाब ब्रिज कटरा से 40 किमी दूर है। यह शहर वैष्णो देवी धाम के लिए प्रसिद्ध है और पहाड़ों की बीच बसा है। यात्रा के बाद यहां की वादियां और स्थानीय बाजारों को घूमने जा सकते हैं। कटरा से वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा करने के साथ ही आप शिवखोरी गुफा मंदिर भी जा सकते हैं। यह एक प्राकृतिक गुफा है जो भगवान शिव को समर्पित है। यहां ट्रेकिंग और अध्यात्म दोनों का अनुभव मिलता है।

पटनीटॉप

कश्मीर के उधमपुर जिले में पटनीटॉप स्थित है, जो कि बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहां घने जंगलों, पहाड़ों और दूर तक फैले हरे–भरे घास के मैदानों का मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। एडवेंचर पसंद लोगों के लिए यह जगह परफेक्ट है। आप स्कीइंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, जिप लाइनिंग और घुड़सवारी जैसी एक्टिविटी का लुत्फ उठा सकते हैं।

सलाल डैम और झील

चिनाब रेलवे ब्रिज से लगभग 50 किमी दूर सलाल डैम स्थित है। यह डैम चेनाब नदी पर बना है और इसका शांत वातावरण मन मोह लेता है। पिकनिक और फोटोशूट के लिए बढ़िया जगह है। झील का मनोरम दृश्य भी आपकी ट्रिप को यादगार बना सकती है।

डोडा

जम्मू कश्मीर में एक बेहद शांत, खूबसूरत और सुकून भरा स्थान डोडा जिला है। यहां भाल पादरी का मनोरम दृश्य आपको बार–बार आने के लिए मजबूर कर देगा। माता चंडी मंदिर स्थित है और सूफी गांव को भी घूमने जा सकते हैं।

क्या है पाइनएप्पल डेटिंग? युवाओं के बीच तेजी से वायरल हो रहा ये नया ट्रेंड

आंखों ही आंखों में इशारा हो गया. ....ये उस समय का गाना है, जब आंखों ही आंखों में इशारे होने के बाद प्यार हो जाता था। समय बदला और फिर ट्रेंड आया लाइक्स और कमेंट्स का। उसमें लोग एक–दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो करते थे, एक–दूसरे की तस्वीरों पर लाइक और कमेंट करके इंप्रेस करते थे। फिर समय में बदलाव आया और लोग एप्स के माध्यम से एक–दूसरे को डेट करने लगे। पर, अब 2025 में डेटिंग ट्रेंड पूरी तरह से बदल गया है। आज के समय में एक अनानास यानी कि पाइनएप्पल लोगों को उनका पार्टनर तलाश करने में उनकी मदद कर रहा है। सुनने में भले ही अजीब लग रहा हो, लेकिन ये सच है। दरअसल, जब डेटिंग के दौरान अनानास का इस्तेमाल हो, तो उसे ही पाइनएप्पल डेटिंग कहते हैं। इस बारे में अभी ज्यादा लोग नहीं जानते है, इसलिए हम आपको इसकी जानकारी देंगे।

पाइनएप्पल डेटिंग क्या है?

सबसे पहले ये जान लें कि इस डेटिंग की शुरुआत स्पेन से हुई थी। इसमें लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं तो अपने शॉपिंग कार्ट में एक पाइनएप्पल रख लेते हैं। ये पाइनएप्पल उल्टा रखा जाता है। इससे वहां मौजूद लोगों को ये संदेश जाता है कि शॉपिंग कार्ट में पाइनएप्पल रखने वाला व्यक्ति सिंगल है। यानि कि वो नए पार्टनर की तलाश में है। इस दौरान यदि सुपरमार्केट कोई दो लोग उल्टे पाइनएप्पल के साथ पाए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि मैच मिल गया। इसके बाद वो दोनों एक–दूसरे से बातचीत करके अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं। ये ट्रेंड सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से फैल रहा है।

क्या हैं इसके फायदे

अब ये जानना आपके लिए काफी जरूरी है कि आखिर इस पाइनएप्पल डेटिंग का फायदा क्या है। दरअसल, ये डेटिंग ऐप्स के बजाय वास्तविक और स्वाभाविक मुलाकातों को बढ़ावा देता है। इसमें लोग सुपरमार्केट जैसी सार्वजनिक जगहों पर मिलते हैं, जिस वजह से किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना थोड़ी कम हो जाती है।

नुकसान भी जान लें

फायदे के बाद पाइनएप्पल डेटिंग के नुकसान भी आपके लिए जरूरी है। दरअसल, अनजान लोगों से मिलना कभी–कभी जोखिमपूर्ण हो सकता है। इसलिए यदि आप पाइनएप्पल डेटिंग के जरिए किसी से मिल भी रहे हैं, तो एकदम से उससे अपनी सारी जानकारी साझा न करें। ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है।

ढोकला

गर्मी के मौसम में लोग हल्के–फुल्के पकवानों का सेवन करना पसंद करते हैं। इन पकवानों में ढोकला भी शामिल है। बेसन से बनने वाला ये गुजराती व्यंजन सुबह से नाश्ते से लेकर शाम की चाय के साथ तक के साथ खाया जाता है। ढोकला बाजार में आसानी से मिल जाता है, लेकिन ज्यादातार लोग इसे घर पर बनाना पसंद करते हैं। यदि आप भी इसे घर पर बनाते हैं, लेकिन ये स्पंजी नहीं बनता है तो ध्यान दें कि कहीं आप भी तो कुछ छोटी–छोटी गलतियां नहीं कर रही हैं। यहां हम आपको इसी बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, ताकि आप घर पर आसान विधि से एकदम बाजार जैसा ढोकला बना सकें।

बैटर का सही न होना

ढोकले का बैटर बनाते समय ये ध्यान रखें कि ये न तो ज्यादा पतला होना चाहिए और न ही ज्यादा गाढ़ा। यदि आपका बैटर काफी ज्यादा गाढ़ा होगा, तो इससे ढोकला एकदम टाइट हो जाएगा। इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी सही रखें। ये ऐसा हो, कि जब इसे आप ढोकला पैन में डालें तो ये चिपके नहीं और आसानी से फिसल जाए, लेकिन इतना भी पतला न हो कि तुरंत बह जाए।

इनो और बेकिंग सोडा डालने का सही समय न देखना

यदि आप गलत समय पर इनो या फिर बैकिंग सोडा डालेंगे तो इससे भी ढोकला एकदम टाइट हो जाएगा। ये आपको तब डालना होता है, जब बैटर पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि इन्हें डालकर तुरंत अच्छे बैटर को हल्का मिक्स करके स्टीमर में रख दें। इसे ज्यादा न फेंटे। ज्यादा फेंटने पर इसका असर खत्म हो जाएगा। इसलिए इनो और बेकिंग सोडा को सही समय पर डालें।

फर्मेंटेशन न करना

आजकल लोग इंस्टेंट ढोकला बनाते हैं, जिसमें फर्मेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सिर्फ सोडा या फिर इनो के इस्तेमाल से ढोकला टाइट हो सकता है।

संक्षिप्त खबरें

यूपी को निवेश का पहला विकल्प बनाने पर काम कर रहे – मुख्य सचिव

लखनऊ, संवाददाता। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि यूपी को हमेशा दूसरे विकल्प के रूप में देखा गया है। हैदराबाद में स्पेस न मिलने पर इन्वेस्टर यूपी में आते थे। अब यूपी को पहले विकल्प के रूप में बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। पिछले सात आठ साल में जीडीपी को दोगुना करने वाले उदाहरण दुनिया में बहुत कम हैं। इस दौरान यूपी की आबादी में चार करोड़ नए लोग शामिल हुए हैं। प्रति व्यक्ति आय भी दोगुना हुई है। 600 डालर से 1400 डॉलर हो गई। अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मुख्य सचिव ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) कॉनक्लेव में निवेशकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने निवेश के लिए कस्टमाइज्ड पॉलिसी बनाई है इसीलिए आज दुनिया से निवेशक यहां आना चाहते हैं। सात आठ साल पहले भी इंडस्ट्रीज थी लेकिन आज जैसा आकर्षण नहीं था। यूपी को लेकर सोच में बदलाव पहले नहीं था। पहले पॉलिसी थी लेकिन इनसेंटिव नहीं होता था। निवेशक कहते थे कि पॉलिसी तो है लेकिन पैसा देने के समय पीछे हो जाते हैं लेकिन यूपी ने इसे कर दिखाया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि दुबई में फिशरीज की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी जहां पानी नहीं है लेकिन ऐसा संभव हुआ। इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर में अंतर है। हमें टियर टू और टियर थ्री सिटीज पर फोकस करना है। सरकार बहुत लंबे समय के लिए काम कर रही है। आजादी के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाद बुंदेलखंड में 65000 हेक्टेयर का नया शहर बनाया जा रहा है। अभी तक 18000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। इंटीग्रेटेड मैन्युफेक्चरिंग क्लस्टर के लिए 6000 एकड़ जमीन ली जा चुकी है।

प्रदेश की 40 स्पेशल ट्रेनें बनाई जाएंगी रेगुलर

लखनऊ, संवाददाता। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे 25 स्पेशल ट्रेनों को रेगुलर बनाकर चलाने की तैयारी कर रहा है। इससे पूर्व 40 ट्रेनों को रेगुलर किया जा चुका है। रेगुलर बन जाने से किराया कम हो जाएगा। ट्रेनें शाहजहांपुर, कानपुर, अयोध्या, बालामऊ रूट की हैं। उत्तर, पूर्वोत्तर व उत्तर मध्य रेलवे प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों को रेगुलर (सामान्य) बनाकर चलाने की योजना जनवरी में बनाई गई थी। इन ट्रेनों के नंबर जीरो के बजाय सामान्य नंबरों से शुरू होंगे। स्पेशल ट्रेनों का किराया अधिक होता है, जबकि रेगुलर का कम। ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए जब पहली जनवरी से ट्रेनों की नई समय सारिणी लागू हुई थी तो उत्तर रेलवे प्रशासन ने 40 स्पेशल ट्रेनों को सामान्य बना दिया था। ट्रेनों को कोरोना के समय से ही स्पेशल बनाकर चलाया जा रहा था। उनके सामान्य हो जाने से किराया करीब आधा हो गया था। ऐसे में अब दूसरे चरण में रेलवे प्रशासन 25 और ट्रेनों को रेगुलर बनाने की तैयारी कर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जुलाई से स्पेशल ट्रेनें रेगुलर के तौर पर पटरी पर उतर आएंगी। इससे तकरीबन 15 हजार यात्रियों को प्रतिदिन राहत मिलेगी। ये ट्रेनें अयोध्या, बाराबंकी, शाहजहांपुर, बालामऊ रूट की होंगी।

हिल स्टेशन की सैर पर वेटिंग की मार

लखनऊ, संवाददाता। ट्रेनों की लंबी वेटिंग से गर्मी की छुट्टियों का मजा किरकिरा हो रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू जाकर पर्वतों की सैर की योजना पर पानी फिर रहा है। वेटिंग का आंकड़ा 146 तक पहुंच गया है। वहीं विमानों का किराया भी महंगा होने लगा है। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। ऐसे में अभिभावकों ने बच्चों संग हिल स्टेशनों की सैर की योजना बनाई, लेकिन ट्रेनों में वेटिंग के चलते उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। लखनऊ से देहरादून जाने वाली कुंभ एक्सप्रेस की स्लीपर में मंगलवार, बुधवार व बृहस्पतिवार को सीटें फुल हैं। थर्ड एसी में क्रमशः 24, 35, 30 वेटिंग चल रही है। वाराणसी देहरादून एक्सप्रेस की स्लीपर में रिग्रेट चल रहा है तथा थर्ड एसी में सोमवार को 25 वेटिंग व उसके आगे सीटें फुल हैं। वहीं वंदेभारत एक्सप्रेस की चेयरकार में मंगलवार, बुधवार व बृहस्पतिवार को 86, 118, 82 वेटिंग चल रही है। लखनऊ से काठगोदाम जाने वाली जंक्शन काठगोदाम एक्सप्रेस की स्लीपर में बुधवार को 146 एवं थर्ड एसी में 86 वेटिंग है। बाघ एक्सप्रेस की स्लीपर फुल है तथा थर्ड एसी में अगले तीन दिन 39, 43, 45 वेटिंग है।

146 तक पहुंची वेटिंग, विमानों का किराया भी महंगा

स्लीपर फुल, एसी में वेटिंग

हिमाचल प्रदेश जाने के लिए लखनऊ से पठानकोट जाने वाली अमरनाथ एक्सप्रेस की स्लीपर में 99, थर्ड एसी में 31 वेटिंग है। बेगमपुरा की स्लीपर फुल है, थर्ड एसी में भी सीटें नहीं हैं। कोलकाता–जम्मूतवी एक्सप्रेस की स्लीपर अगले तीन दिन फुल है, थर्ड एसी में 32, 27, 28 वेटिंग चल रही है। लखनऊ से गुवाहाटी जाने वाली गोमतीनगर कामाख्या एक्सप्रेस की स्लीपर में सोमवार को 72 व थर्ड एसी में 65 वेटिंग है।

शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करने पर छात्रा का अश्लील वीडियो किया वायरल

लखनऊ, संवाददाता। बीबीडी इलाके में छात्रा ने शारीरिक संबंध बनाने से इन्कार किया तो दो छात्रों ने उसका अश्लील वीडियो वायरल कर दिया। रविवार को बीबीडी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा में एफआईआर दर्ज की है। छात्रा के मुताबिक 2024 में वह बीबीडी स्थित एक कॉलेज में कक्षा नौ में पढ़ती थी। उस दौरान उसकी दोस्ती दसवीं के दो छात्रों से हुई थी। एक ही हॉस्टल में रहने के कारण इनमें से एक छात्र से गहरी दोस्ती हो गई थी। वर्ष 2025 में हाईस्कूल पास करने के बाद छात्रा ने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन आरोपियों से मुलाकात होती रही। इस बीच आरोपी ने धोखे से उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। छात्रा ने बताया कि नवंबर 2024 में उसने दोनों आरोपियों से कुछ रकम ली थी, जिसे लौटा भी दिया था। पीड़िता का आरोप है कि गत एक जून को दोनों आरोपियों ने उसे कॉल कर गोरखपुर आने और शारीरिक संबंध बनाने की बात कही। विरोध पर दोनों आरोपी इंस्टाग्राम पर उससे अश्लील बातें करने लगे। उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के साथ ही उसके पिता को भेज दिया। इंस्पेक्टर राम सिंह ने बताया कि मामले की विवेचना चल रही है।

टैक्स चोरी का नेटवर्क चला रहा ट्रांसपोर्ट सिंडिकेट

लखनऊ, संवाददाता। अफसरों के संरक्षण में दलालों और ट्रांसपोर्टरों के सिंडिकेट से हर महीने करोड़ों की टैक्स चोरी का माल दूसरे राज्यों से आ रहा है। अधिकतर गाजियाबाद, आगरा व मथुरा के रास्ते आने वाले माल में रेडीमेड, इलेक्ट्रिकल, होजरी, पान मसाला सहित दो दर्जन से ज्यादा उत्पाद शामिल हैं। इसके पीछे दिल्ली, गाजियाबाद और कानपुर के ट्रांसपोर्टरों की भूमिका है। एक तरफ प्रदेश में टैक्स चोरी रोकने के लिए सख्ती बरती जा रही वहीं, दूसरी तरफ अन्य राज्यों से आने वाले टैक्स चोरी के उत्पादों की आवक बढ़ गई है। कर चोरी के उत्पादों की आवाजाही पर कुछ अंकुश लगा है लेकिन इसकी भरपाई दिल्ली, राजस्थान सहित अन्य राज्यों से हो रही है। इसमें कुछ ऐसे कारोबारी भी हैं जो टैक्स चोरी में लिप्त थे लेकिन सख्ती होने पर एक इकाई अन्य राज्यों में खोल ली और वहां से फर्जी ई वे बिलों और बिल बाउचर से माल यूपी भेज रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के लगभग 125 ट्रांसपोर्टरों के सिंडिकेट का संचालन पश्चिमी यूपी का एक चर्चित दलाल कर रहा है। इस श्पूल में कुछ विभागीय अधिकारी भी शामिल हैं। कर चोरी के माल से लटे इन उत्पादों की सेफ डिलीवरी के एवज में हर महीने करोड़ों रुपये ट्रांसपोर्टर देते हैं। दूसरा सिंडिकेट गाजियाबाद रूट क जहां से माल आ रहा है। इस सिंडिकेट है, के एक बड़े दलाल के संबंध एक मंत्री स् बताए जाते हैं। यूपी के रास्ते अन्य राज्य में जाने वाले ट्रकों को भी श्सेफ रूट दिया जा रहा है। इस वजह से राज्य के कारोबारियों के सामने भी समस्या खड़ हो गई है क्योंकि उन्हें डर है कि टैक्स चोरी के रास्ते आना वाला माल उनके बाजार में सेंध न लगा दे।

लखनऊ के विकास के लिए मांगे 10 हजार करोड़, 16वें वित्त आयोग की बैठक में प्रतिनिधि ने की मांग

लखनऊ, संवाददाता। राजधानी लखनऊ आज ऐसे दौर से गुजर रही है, जहां उसकी भौगोलिक सीमाएं और जनसंख्या दोनों ही अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है। इस विस्तार ने नगर को प्रगतिशील दिशा में ले जाने की संभावनाओं को बढ़ाया है, साथ ही संसाधनों की उपलब्धता पर भारी दबाव भी डाला है। ऐसे में अब शहर के विकास के लिए नगर निगम ने 16वें वित्त आयोग से लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की विशेष सहायता की मांग की है। जनसंख्या और क्षेत्रफल में हुई तेज वृद्धि रू शहर के होटल में हुई आयोग की बैठक में नगर निगम का प्रतिनिधित्व पार्षद अरुण तिवारी ने किया। उन्होंने बैठक में बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, लखनऊ नगर की जनसंख्या 28.17 लाख थी। वर्तमान में यह आंकड़ा लगभग 48.60 लाख है। इसी प्रकार, नगर निगम का कुल क्षेत्रफल भी 310 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर अब 568 वर्ग किलोमीटर हो चुका है। उन्होंने बैठक में कहा कि नगर निगम ने विस्तारित क्षेत्रों के प्रभावी विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार लगभग 7207 करोड़ रुपये की आवश्यकता बताई है। इसके अतिरिक्त नगर की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए 3500 करोड़ रुपये की अलग मांग की गई है।

बढ़ते क्षेत्रफल और जनसंख्या से उपजीं समस्याएं

बैठक में पार्षद अरुण तिवारी ने बताया कि विस्तारित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं जैसे जल आपूर्ति, सड़क, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्क, स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक प्रबंधन जैसी सेवाओं का व्यापक अभाव है। 83 प्रतिशत नए क्षेत्र जोड़े गए हैं, लेकिन वहां आज भी न तो पर्याप्त नाले हैं, न सीवर लाइनें, और न ही समुचित पेयजल व्यवस्था। इस कारण शहर के केंद्र से दूर बसी नई कॉलोनियों के लाखों लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे में वर्तमान आवश्यकताओं के मद्देनजर और उन्नत तकनीक आधारित व्यवस्था को लागू करने के लिए आगामी वित्त आयोग में और अधिक संसाधनों की आवश्यकता है।

इसके तहत वेस्ट–टू–एनर्जी प्लांट, घरेलू हानिकारक अपशिष्ट व ई–वेस्ट के लिए कलेक्शन सेंटर, मल्टी लेयर प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट, सैनिटेशन रिसोर्स पार्क, पब्लिक ई–चार्जिंग स्टेशन, नगर निगम कार्य हेतु ई–व्हीकल्स, नगर निगम भवनों पर सोलर पैनल जैसी परियोजनाओं को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है।

पीएम फियामे की सरकार गिरने के बाद समोआ में चुनाव की तारीख की घोषणा

न्यूकैसल, एजेंसी। प्रधानमंत्री फियामे नाओमी माताफा की सरकार गिरने के बाद समोआ में चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। 29 अगस्त को समोआ में छह महीने पहले चुनाव होंगे। यह चुनाव इसलिए हो रहे हैं कि पिछले महीने संसद में बजट पास नहीं पाया था, जिसके कारण पीएम फियामे की सरकार गिर गई थी। फियामे ने साल 2021 में समोआ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचा था। उन्होंने मानवाधिकार संरक्षण पार्टी (एचआरपीपी) को हराकर चार दशक के शासन को समाप्त कर दिया था। अब एक त्रिकोणीय राजनीतिक लड़ाई का सामना कर रही हैं, जिसका असर समोआ के बाहर के देशों पर भी पड़ सकता है।

चीन–ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका अपना असर बढ़ाने का प्रयास कर रहे

समोआ में अचानक चुनाव ऐसे समय में हो रहा है, जब दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में भू–राजनीतिक रुचि बढ़ गई है। चीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देश यहां अपना असर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और समोआ को एक अहम रणनीतिक देश माना जा रहा है। समोआ की आबादी 200,000 है। यह देश समुद्र के बढ़ते स्तर की वजह से जलवायु परिवर्तन के खतरों से सबसे ज्यादा प्रभावितों में से एक है।

पार्टी अध्यक्ष को कैबिनेट से निकालने के बाद शुरू हुआ विभाजन

इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री फियामे की पार्टी में अंदरूनी झगड़ा शुरू हो गया था। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष लाश्उली लेउतेया पोलाताइवाओ को आपराधिक आरोपों के चलते कैबिनेट से निकाल दिया था, जिससे पार्टी में फूट पड़ गई। हालांकि, फियामे दो बार अविश्वास मतों से बच गईं, लेकिन HRPP और FAST के कुछ बागी नेताओं ने मिलकर उनके बजट को रोक दिया। इसके चलते समय से पहले चुनाव कराने पड़े।

फियामें अब समोआ यूनाइटिंग पार्टी का नेतृत्व कर रहीं

फियामे अब नवगठित समोआ यूनाइटिंग पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं। चुनाव में उनका सामना अब उनके पूर्व बॉस तुइलाश्एपा सैश्इलेले मालीलेगाओई की एचआरपीपी और लाश्उली की रीब्रांडेड थ्ैज से है। देश के सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव की तैयारी के लिए ज्यादा समय देने की अपील को ठुकरा दिया। इसके बाद देश के प्रमुख नेता तुइमालेलिफानो सुआलौवी वैलेटोआ द्वितीय ने मंगलवार को औपचारिक रूप से चुनाव की तारीख की घोषणा की।

कनाडा अगले साल तक पूरा करेगा नाटो का रक्षा खर्च लक्ष्य

टोरंटो, एजेंसी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सोमवार को कहा कि उनका देश 2026 की शुरुआत तक नाटो के सैन्य खर्च के 2: जीडीपी वाले लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहले यह लक्ष्य दशक के अंत तक हासिल करने की योजना थी। कार्नी ने टोरंटो विश्वविद्यालय में दिए एक भाषण में कहा कि हमारा सैन्य ढांचा और उपकरण पुराने हो चुके हैं, जिससे हमारी तैयारियों में बाधा आ रही है। हमारी चार में से सिर्फ एक पनडुब्बी चालू हालत में है। हमारी नौसेना और जमीनी वाहन भी आधे से कम ही काम कर रहे हैं।

अमेरिका पर अधिक निर्भरता घटना पर जोर

पीएम कार्नी ने कनाडा के रक्षा उपकरणों के लिए अमेरिका पर अधिक निर्भरता को लेकर चिंता जताई।

उन्होंने कहा कि कनाडा रक्षा उपकरणों के लिए अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसे अब बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर अधिक निर्भरता घटाने के लिए हम अपनी रक्षा पूंजी का तीन–चौथाई हिस्सा जो अमेरिका को भेजते हैं, अब नहीं भेजा जाएगा। कार्नी ने आगे कहा कि शीत युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया का प्रमुख ताकतवर देश रहा, लेकिन अब उसका वर्चस्व कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका अपने बाजारों तक पहुंच और सुरक्षा का शुल्क वसूल रहा है। ऐसे में हम अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएंगे। बता दें कि ट्रंप के साथ टैरिफ विवाद के बाद से कार्नी अमेरिके की नीतियों के खिलाफ सख्ती से पेश होते नजर आ रहें हैं। जहां अब कार्नी सरकार अब यूरोपीय संघ के साथ साझेदारी बढ़ा रही है।

अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ और ट्रंप के जन्मदिन पर होगी सैन्य परेड

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में शनिवार को अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 79वां जन्मदिन मनाने की तैयारी हो रही है। इस मौके पर सैन्य परेड होगी। इसके लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। 18 मील इलाके में फेंसिंग की गई हैं। जबकि 175 मैग्नेटोमीटर लगाए गए हैं। सीक्रेट सर्विस के वॉशिंगटन फील्ड ऑफिस के मैट मैककूल ने कहा कि हम भारी भीड़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। 18 मील से अधिक एंटी–स्केल फेंसिंग लगाई जाएगी। जबकि कई ड्रोन हवा में होंगे। कोलंबिया का पूरा जिला आमतौर पर ड्रोन के लिए नो–फ्लाई जोन होगा। सीक्रेट सर्विस के वॉशिंगटन फील्ड ऑफिस के मैट मैककूल ने कहा कि हम भारी भीड़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। 18 मील से अधिक एंटी–स्केल फेंसिंग लगाई जाएगी। जबकि कई ड्रोन हवा में होंगे। कोलंबिया का पूरा जिला आमतौर पर ड्रोन के लिए नो–फ्लाई जोन होगा। सेना के अधिकारियों का अनुमान है कि शाम की सैन्य परेड में लगभग दो लाख लोग शामिल होंगे। मैककूल ने कहा कि हम लाखों लोगों के लिए तैयार हैं। हमारे पास एक टन मैग्नेटोमीटर है। अगर दस लाख लोग आते हैं, तो हमें कुछ लाइनें लगानी पड़ेंगी।

दिन में मनेगा जन्मदिन, रात में होगी परेड

कार्यक्रम के दौरान दिन में ट्रंप का जन्मदिन समारोह मनाया जाएगा। जबकि रात के वक्त सैन्य परेड होगी। इसके लिए सुरक्षा चौकियों पर 175 मैग्नेटोमीटर लगाए जाएंगे। मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग की प्रमुख पामेला स्मिथ ने कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। उन्होंने कहा कि लोग कार्यक्रम में समय से पहले आएं।

सिंगापुर में 1800 साल पुराने श्री सिवन मंदिर में भव्य अभिषेक समारोह

सिंगापुर, एजेंसी। सिंगापुर के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में शामिल श्री सिवन मंदिर अभिषेक समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान 1,800 की शताब्दी से भी पुराने इस मंदिर में 20,000 से अधिक श्रद्धालु जुटे। राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय मंत्री व गृह मंत्री के. षणमुगम गेलांग ईस्ट मंदिर के नाम से मशहूर मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ शामिल हुए। वह बोले, आज का अभिषेक समारोह महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंगापुर में हिंदू समुदाय के दिल में इस मंदिर का विशेष स्थान है।

षणमुगन ने किया समारोह का अनावरण

षणमुगम ने समारोह की पट्टिका का अनावरण भी किया। सुबह 7 बजे से ही मंदिर के बाहर विशेष रूप से बनाए गए तंबुओं में पहुंचे श्रद्धालु महाकुंभाभिषेकम का बेसब्री से इंतजार करने लगे।

यह मंदिर की छत पर बर्तनों से पवित्र जल डालने की प्रक्रिया है। कुंभम कहे जाने वाले पात्रों में जल भरा जाता है और लगातार सात दिन तक संस्कृत मंत्रों के जाप के माध्यम से इन्हें ऊर्जाप्रदान की जाती है। द स्ट्रेट्स टाइम्स के मुताबिक, हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड ने कहा कि मंदिर में 26 जुलाई तक 48 दिन प्रार्थना, अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

2018 के हमले के बाद हिरासत में लिए गए इस्लामिक स्टेट के नौ आतंकियों को फांसी

तेहरान, एजेंसी। ईरान ने 2018 के हमले के दोषियों पर कार्रवाई को लेकर बयान जारी किया। ईरान ने कहा कि हमले के बाद हिरासत में लिए गए इस्लामिक स्टेट समूह के नौ आतंकियों को फांसी दे दी गई है। ईरानी न्यायपालिका की समाचार एजेंसी ने मंगलवार को फांसी की घोषणा की। इसमें कहा गया कि आतंकियों को ईरान के अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड के साथ झड़प में शामिल होने के बाद हिरासत में लिया गया था। इसमें तीन सैनिक मारे गए थे। ईरान में फांसी के बाद मृत्युदंड दिया जाता है। इस्लामिक स्टेट ने 2014 में खिलाफत के तहत इराक और सीरिया के विशाल भूभाग पर कब्जा कर रखा था। इसने अमेरिकी नेतृत्व वाली सेनाओं द्वारा परास्त कर दिया था। अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान के जरिये पश्चिमी समर्थित सरकार के पतन के बाद से इस्लामिक स्टेट की ताकत बढ़ी है। इस्लामिक स्टेट ने पहले जून 2017 में तेहरान में संसद और अयातुल्ला रूहोल्लाह खुमैनी की समाधि पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसमें कम से कम 18 लोग मारे गए थे और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस्लामिक स्टेट ने ईरान में अन्य हमलों की भी जिम्मेदारी ली है। इसमें 2024 में दो आत्मघाती बम विस्फोट शामिल हैं। जो 2020 के अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए एक ईरानी जनरल की याद में किए गए थे। उस हमले में कम से कम 94 लोग मारे गए थे। मार्च में इस्लामिक स्टेट के प्रमुख अब्दल्लाह माकी मोसलेह अल–रिफाई को मार गिराया गया था।

जैविक सामग्री की तस्करी के आरोप में एक और चीनी वैज्ञानिक गिरफ्तार

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में अवैध जैविक सामग्री की तस्करी मामले में एक और चीनी वैज्ञानिक को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा में क्षेत्रीय प्रमुख जॉन नोवाक ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार को अमेरिका पहुंचते ही डेट्रॉयट हवाई अड्डे पर चीनी वैज्ञानिक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एफबीआई ने बताया कि गिरफ्तार चीनी वैज्ञानिक वुहान में हुआझोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांस डिग्री हासिल कर रही हैं। उसने मिशिगन यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए एक साल बिताने की योजना बनाई थी। इस वैज्ञानिक पर आरोप है कि उन्होंने महीनों पहले मिशिगन विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में कर्मचारियों को जैविक सामग्री भेजी थी। एफबीआई ने मामले में अदालत में दाखिल अपने दस्तावेज में कहा है कि यह सामग्री कुछ खास किस्म के फंगस से संबंधित है। इसके लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। वहीं,जॉन नोवाक ने कहा कि शोध उद्देश्यों के लिए अमेरिका में जैविक सामग्री के आयात के दिशानिर्देश कड़े लेकिन स्पष्ट हैं। इस तरह की तस्करी से अन्य अतिथि शोधकर्ताओं के वैध कार्य को कमजोर होते हैं और उन्हें संदेह का सामना करना पड़ता है।

देश की उपासना
(हिन्दी साप्ताहिक)

स्वात्वाधिकारी की ओर से मेसर्स प्रभु दयाल प्रकाशन के लिए प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक पी.सी. श्रीवास्तव द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर (उ0 प्र0) से मुद्रित तथा ई–3464, राजाजीपुरम (मिनी स्टेडियम के पास) लखनऊ (उ0प्र0) से प्रकाशित।

सम्पादक
पी.सी. श्रीवास्तव
मो. 7007415808
9415034002

समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने स्रोत एवं संकलन है। जिसमें सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

नोट : उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयं सेवी है। तथा समाचार से सम्बन्धित सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।

खबरों के लिए ई–मेल का प्रयोग करें–
deshkiupasanadailynews@gmail.com
dkunews01@gmail.com

पंजीकृत कार्यालय–उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर (उ0प्र0) 7007415808 / 9415034002